

SHRI SURESH A. KESWANI: Sir, my question is about modification of the service rules.

MR. CHAIRMAN: Please. No, no. That is all right. Mr. M.N. Das.

DR. M.N. DAS: We have a difficult state of the economy in the country. Is the hon. Minister aware of the fact that ticketless travelling has become almost a normal feature in some railway zones of the country? If the Minister is aware of the fact, is he contemplating any effective steps or measures to stop this malpractice in order to save immense loss of revenue to the national exchequer?

श्री नीतीश कुमार: इस साल के बजट में टिकटलेस ट्रेवलिंग पर पैन्टली की रकम 50 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये करने का प्रस्ताव रखा है तथा मेरा विचार है कि यदि यह सचन प्रक्रिया टिकटलेस ट्रेवलिंग के खिलाफ चलाई जाए तो रिवेन्यू का लीकेज रुकेगा तथा टिकट लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों को पर्याप्त सुविधा मिल सकेगी।

प्रो० रामगोपाल यादव: हमारे माननीय मंत्री जी ने अभी जवाब देते हुए कहा है कि मिनिस्टर्स को, रेल मंत्री को डिस्क्रीमिनेशनरी पास देने का भी अधिकार है। मैं जानता हूँ कि ये पास गाइडलाईंस के हिसाब से दिए जाने चाहिए लेकिन उससे हटकर डिस्क्रीमिनेशनरी पास दिए जाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि आपने और आपसे पहले जो मंत्री थे उन्होंने कितने डिस्क्रीमिनेशनरी पास जारी किए? क्या यह सच है कि इससे पहले एक ही राज्य या एक ही जिले के लोगों के 60 और 70 प्रतिशत पास जारी किए गए थे?

श्री नीतीश कुमार: सभापति महोदय, अभी इस विषय में सूचना रेडिली अवेलेबल नहीं है परंतु मैं यह बताना चाहता हूँ कि 1.4.95 से 31.12.95 के बीच जो कार्ड इश्यू किए गए उनकी संख्या 407 थी तथा चेक पासों की संख्या लगभग 3300 थी।

प्रो० रामगोपाल यादव: जो प्रश्न मैंने पूछा मंत्री महोदय उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं।

श्री नीतीश कुमार: मैंने 1995 के आंकड़े बताए, यदि आप 1996 के आंकड़े जानना चाहते हैं तो मैं बताना चाहता हूँ कि 1.4.1996 से 31.12.1996 तक 265 जमा 315 कार्ड पास इश्यू किए गए थे तथा 1334 जमा 1827 पास इश्यू किए गए थे। 1.4.97 से

31.12.97 तक 319 कार्ड पास इश्यू किए गए थे तथा चेक पास 5247 जमा 1757 इश्यू किए गए थे। 1.4.98 से 31.12.98 तक 106 कार्ड पास इश्यू किए गए हैं तथा 112 जमा 9 चेक पास इश्यू किए गए हैं।

*63. [The questioner (Shri S.M. Krishna) was absent. For answer, vide col. 28 infra.]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बेचे जाने वाले खाद्यान्नों की मात्रा

@*64. श्री बरजिन्दर सिंह:

श्री राज मोहिन्दर सिंह:†

क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बेचे जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा से राशन कार्डधारी परिवार की आवश्यकताएँ पूरी नहीं होती हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से राशन कार्डधारी परिवार की केवल आंशिक आवश्यकता ही पूरी हो रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और सरकार द्वारा राज्यों को खाद्यान्न का कोटा किन-किन आधारों पर आवंटित किया जाता है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्री (श्री सुब्रजित सिंह बरनाला): (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हाँ। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचे गए खाद्यान्नों की मात्रा राशन कार्ड धारक परिवार की समस्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती है।

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जारी होने वाले खाद्यान्नों की मात्रा वसूल किए गए खाद्यान्नों की मात्रा पर निर्भर करती है। इस प्रकार उपलब्ध होने वाली

@सारांकित प्रश्न सं० 64 और 72 साथ-साथ लिए गए।

†सभा में यह प्रश्न श्री राज मोहिन्दर सिंह द्वारा पूछा गया।

खाद्यान्न की कुल मात्रा में से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्न को जारी करने के अलावा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार बफर स्टॉक को भी बनाए रखना होता है और "मिड-डे-मील" योजना के अधीन खाद्यान्न जारी करने जैसी वचनबद्धताएं भी पूरी करनी होती हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली खुले बाजार का विकल्प नहीं है बल्कि यह केवल इसकी अनुपूरक है।

जून, 1997 में लागू की गई लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए खाद्यान्न का आवंटन गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए 10 किलोग्राम प्रति परिवार प्रतिमाह की दर से आवश्यकता को हिसाब से लेने के बाद विगत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन हुए औसत वार्षिक उठान के आधार पर निर्धारित किया गया है।

इस प्रकार निर्धारित आवंटन के अलावा, आवश्यकता तथा केन्द्रीय पूल में खाद्यान्न की उपलब्धता और खाद्य सन्निधि संबंधी बाधाओं को ध्यान में रखकर राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त आवंटन भी किए जाते हैं।

श्री राज मोहिन्दर सिंह: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहता हूँ कि पीडीएस योजना जिस लक्ष्य को लेकर शुरू की गई थी, वह लक्ष्य पूरा नहीं किया गया है। मिनिस्टर साहब ने अभी बताया कि एक फैमिली को एट दि रेट ऑफ दस किलो पर मंथ के हिसाब से दिया जाता है। हम जमींदार लोग सारे उग्र खेतों करते रहे हैं। खेती करने वाले एक व्यक्ति को हम एक मन अनाज देते हैं तो एक फैमिली जिसके सदस्यों की संख्या पांच है उसे दो क्विंटल एक मंथ के लिए चाहिए, तो क्या इस सिस्टम के तहत दस किलो अनाज में उस फैमिली का गुज़ारा हो सकता है? अतः यह सिस्टम बिल्कुल गलत है। इस योजना के तहत जो संस्थाएं गांव में अनाज डिस्ट्रीब्यूट करने जाती हैं वे गांव में जाती ही नहीं हैं तथा घर बैठे ही लोगों के अंगूठे कागजों पर लग जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसकी इक्वायरी की जाए। मिनिस्टर साहब का इस संबंध में क्या जवाब है?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला: यह सही है कि दस किलोग्राम में एक परिवार का गुज़ारा नहीं हो सकता, उसे अंदाज़न 73 किलो चाहिए। एक महीने के लिए एक फैमिली को 73 किलो चाहिए, यह अंदाज़ा है। दस किलो से गुज़ारा नहीं होता है। दस किलो से सपोर्ट होता है। दस किलो बहुत थोड़े दाम पर दिया जाता है। उनको सपोर्ट करने के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलाया

जा रहा है। उनको जो पूरी जरूरत है वह इसको पूरी नहीं कर सकता है।

श्री राज मोहिन्दर सिंह: जैसा मिनिस्टर साहब ने कहा दस किलो दिया जाता है। पांच मंथ की फैमिली को दस किलो दिया जाता है, इससे कुछ बात बनने वाली नहीं है। एफसीआई जो पीडीएस का अनाज देने के लिए जिम्मेदार है, इसकी पंजाब में इंडिपेंडेंट इन्क्वायरी करा लीजिए। वहां पर एफसीआई गोदामों का बहुत बुरा हाल है। एफसीआई के गोदामों में अनाज सड़ रहा है, रखा रहा है। उसको गरीबों में बांटने के बजाए खराब कर रहे हैं। एक साल वह अनाज वहां पड़ा रहता है। वह इसकी इक्वायरी करते हैं और अगर सौ टन अनाज सड़ जाता है तो उसकी रिपोर्ट चली जाती है कि एक हजार टन अनाज सड़ गया। आप इसकी इंडिपेंडेंट इक्वायरी करा दीजिए। जो पीडीएस का अनाज एफसीआई में है, इन एजेंसीज की इंडिपेंडेंट इन्क्वायरी होनी चाहिए। इसका आप क्या जवाब देंगे?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला: एफसीआई के गोदामों की बात और है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का एफसीआई गोदामों से कोई ताल्लुक नहीं है। एफसीआई के गोदामों में महज उसको स्टोर किया जाता है और जहां जहां उसकी जरूरत होती है, उसको वहां भेजा जाता है। आग्नेवल मंथर यह सही कह रहे हैं कि एफसीआई के गोदामों की हालत कई जगह बहुत अच्छी नहीं है। कोशिश की जाती है कि उनकी हालत सुधारी जाए। लेकिन इसका इंडिस्ट्रीब्यूशन पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं है।

MR. CHAIRMAN: There are two allied questions, question No. 68 and question No. 72. We will take up them together. Shri Ish Dutt Yadav. Not present. Chaudhary Harmohan Singh Yadav. Not present. Shri N.R. Dasari.

SHRI N.R. DASARI question No. 72.

Implementation of Targeted Public Distribution System

@*72. SHRI N.R. DASARI:
SHRI GAYA SINGH:†

Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that implementation of the targeted Public

† The question was actually asked on the floor of the House by Shrimati Kamla Sinha.